श्री डी० पी० यादव : सभी सम्बन्धित संस्थाओं को इन्वाइट किया जायगा ।

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष जी, हम लोगों ने 1920 में नान-कोआपरेशन मूवमेन्ट चलाया, उस समय से लेकर आज तक देश में एजूकेशन की पद्धति के सम्बन्ध में सरकारी स्तर तथा गैर-सरकारी स्तर पर सैकड़ों मीटिंग्ज हो चुकी हैं, सैकड़ों कोर्स बनाये गये । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आप की यूनीवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन की जो टीचर्स कौन्सिल है क्या उस के लिये चरित्र निर्माण के बारे में कोई क्राइटेरिया कायम करना चाहते हैं । मैं आप के सामने उदाहरण रखता हूं—काशी विद्यापीठ में आचार्य नरेन्द्र देव चटाई पर बैठ कर पढ़ाते थे, बाबू भगवान दास चटाई पर बैठ कर पढाते थे और उन के चरित्र से हम लोगों को इंस्पीरेशन मिलता था और उस के बाद काशी विद्यापीठ के जितने छात्र जेल गये और आज भी मुल्क के लिये सेवा कर रहे हैं, उतने किसी दूसरी संस्था के नहीं गये । मैं जानना चाहता हूं—शिक्षा के माध्यम से चरित्र निर्माण के सम्बन्ध में हमारी सरकार क्या कर रही है । कल हमारे शिक्षा मंत्री जो लाल किले के रैम्पार्ट पर गांधी टोपी लगाये बैठे थे, लेकिन आज गांधी टोपी नहीं लगाये हैं—कल और आज में इतना असर पड गया—इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि चरित्र निर्माण के सम्बन्ध में हमारी सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री डी० पी० यादव : आप का मतलब है शिक्षकों में चरित्र होना चाहिये ।

श्री विभूति मिश्र : शिक्षक और स्टूडैन्ट दोनों में होना चाहिये । आज शिक्षक भी सिगरेट पीता है और स्टूडैन्ट भी सिगरेट पीता है ।

श्री डी० पी० यादव : अध्यक्ष जी, जहां तक शिक्षा में चरित्र का सम्बन्ध है, हम लोगों का हमेशा यही प्रयास रहता है कि इस के इनपुट्स इस में रहें । मैं माननीय सदस्य का बहुत अनुगृहीत हूं, इन से समय समय पर सलाह लेकर मैं बहुत सी योजनायें बनाता रहता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, सरकार ने अध्यापकों को शिक्षित करने के लिये जो कार्यक्रम बनाया है मैं जानना चाहता हूं कि आप प्रतिवर्ष कितने शिक्षकों को इस प्रकार से शिक्षित कर सकेंगे । क्या इस के बारे में आप ने कोई योजना बनाई है, यदि बनाई है तो उसे बतला दीजिये ?

श्री डी० पी० यादव : इस देश में करीब 24 लाख प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक हैं । यदि हम एक दिन में सब को प्रशिक्षित करना चाहें तो यह सम्भव नहीं है । लेकिन केन्द्रीय सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षक अनुसन्धान परिषद् के द्वारा एक नई योजना लाये हैं । हम 15 हजार को—टीचर्स को हर साल प्रशिक्षित करेंगे—कांटेक्ट-कम-कोरस-पोण्डेंस कोर्स के द्वारा । इस सम्बन्ध में और भी कई योजनायें बनाई गई—यदि आप नोटिस देंगे तो बतला सकूंगा ।

Fall in Sugarcane Price in U.P.

*92. SHRI S. M. BANERJEE: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether sugarcane prices have gone down in U.P. as compared to last two seasons;

(b) whether price of sugar is soaring in open market; and

(c) if so, the reasons thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SHAHNAWAZ KHAN): (a) to (c). A statement giving the required information is laid on the Table of the House.

Statement

(a) As reported by the Government of Uttar Pradesh, the following prices of sugarcane were paid by sugar factories in 1973-74, 1974-75 and 1975-76 seasons:—

Season	Prices paid by factories per quintal	
1973-74	Rs. 13.25 for Western and Central U.P. Rs. 12.25 for Eastern U.P.	
1974-75	Rs. 13.25 for Western and Central U.P. Rs. 12.25 for Eastern U.P.	till 6-12-1974
	Rs. 14.50 for Western and Central U.P. Rs. 13.50 for Eastern U.P.	From 7-12-74 till the end of the season
1975-76	Rs. 13.25 for Western and Central U.P. Rs. 12 25 for Eastern	

(b) and (c). A rising trend in the prices of levy-free sugar in the open market was noticed from about June, 1976. This could be attributed, among others, to speculative tendency in the market as a result of the fall in production, limited availability in the market of other sweetening agents, anticipated demands for sugar for the festival seasons, and increase in tariff value of levy-free sugar. In order to arrest the rising trend in prices, Government have released larger quantities of levy-free sugar from time to time and also taken other regulatory measures, to maintain an even flow of the commodity in the open market. In case the situation warrants it, Government have plans ready to release more levy-free sugar.

SHRI S. M. BANERJEE: From the statement it appears that in 1974-75 the price of sugarcane was settled at Rs. 14.50 for Western and Central UP and Rs 13 50 for Eastern UP. In the same statement it is mentioned that in 1975 76 the price was Rs 13 25 for Western and Central UP and Rs 12.25 for Eastern UP The statement further says:

> "A rising trend in the prices of levy free sugar in the open market was noticed from about June, 1976 This could be attributed, among others, to speculative tendency in the market as a result of the fall in production, limited availability in the market of other sweetening agents, anticipated demands for sugar for the festival seasons, and increase in tariff value of levy-free sugar."

I would like to know whether this reduction in price of sugarcane in UP was done at the instance, or at the pressure of, the sugar mill magnates Otherwise, I do not find any reason why there should be this discrimination between Western and Eastern UP Secondly, in 1973 during the time of the Charan Singh Ministry, is it not a fact that the price of sugarcane was Rs 16 per quintal? Who decided to reduce it? Was there any directive from the Centre to the State Government to revise the sugarcane price, at the instance of pressure of the sugar magnates?

SHRI SHAHNAWAZ KHAN The fixation of cane price is done by the Central Government, on the advice of the Agricultural Prices Commission, who work out the actual cost of production of sugarcane, after taking into consideration other factors like the price of levy sugar. The major sugarcane producing States are also consulted. In consultation with all these people the minimum statutory price of sugarcane is fixed.

SHRI S. M BANERJEE My second question was about discrimination between Eastern and Western UP. Is it due to sugar content?

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: It is mainly because of the difference in recovery between eastern and western UP.

SHRI S. M. BANERJEE: In the statement it is mentioned:

> "In order to arrest the rising trend in prices, Government have released larger quantities of levy-free sugar from time to time and also taken other regulatory measures, to maintain an even flow of the commodity in the open market."

They have increased the quantity of sugar for Janmashtami. I am happy about it. But, aparat from the increase in levy sugar, what other steps have been taken to reduce the price of sugar in the open market? I am asking this question because the price of sugar has gone up from Rs. 4-50 to Rs. 5 and it will go up to Rs. 5-25 during Janmashtami. Have Government taken any final decision and are they ready to announce the nationalisation of the sugar factories in UP?

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: Government have fixed 65 per cent of the total production of sugar in the country as levy sugar, to be distributed at the fixed price of 2.15 per kg. The price of free sugar is not fixed and it fluctuates As the House is aware, even out of the excess realisation by sale of free sugar, according to the Bhargava formula, 50 per cent should go to the growers. Therefore, even if the price sometimes exceeds a little bit, firstly there is no statutory level to the upper level of the prices, and secondly, the growers get a share of it

SHRI S. M. BANERJEE: Mr. Speaker, may I have your protection? Am I to understand that there is no ceiling on the price of the sugar sold in the market? This is very damaging statement. It means that the sugar price in the free market can go up to any extent, and Government is helpless. Who fixes the prices, after all? Is it the speculators, the dealers?

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: As I said, 65 per cent of the total production of sugar is taken over by the Government and distributed as levy sugar. There is free sale of the remaining 35 per cent in the market, but when we find that the prices are going up unduly high, we release more levy free sugar in the market, so that the prices come down.

SHRI S M. BANERJEE: Who fixes the price?

MR. SPEAKER: The rest is free.

SHRI S M. BANERJEE: Will it go up to Rs. 10/-?

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: The price should be arrested.

MR. SPEAKER: That is a suggestion.

SHRI SAHANAWAZ KHAN: We arrest it by relasing more levy free sugar.

श्री नरसिंह नारायण पांडे : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यह वसूल बताया कि 35 परसेंट शुगर हम फ्री कोटा में रिलीज करते हैं और यह इसलिए रिलीज करते हैं कि उसके पचास परसेंट से केन ग्रोअर्स का बकाया अदा किया जाए और बाकी से फैक्ट्री अपने लासेज को कम्पेन्सेट करे तथा मिल को ठीक करे। मैं जानना चाहता हूं कि इस पालिसी के अन्तर्गत क्या अभी तक सारे देश में करेन्ट सीजन 1975-76 का 18.67 करोड़ रुपए केन ग्रोअर्स का मिलों के ऊपर बाकी है, 1974-75 का 4.26 करोड़ रुपयों बाकी है और उस के पहले सीजन और उस से भी पहले सीजन का 3.42 करोड़ बाकी है जो करीब 26 करोड़ रुपये होता है? इस तरह से इस का पचास परसेंट उत्तर प्रदेश में बाकी है और उस का सब से ज्यादा हिस्सा ईस्ट यू पी और बिहार में बाकी है? यदि हां, तो इस संबंध में जो आप की पालिसी

है उसको देखते हुए आप ने क्या पीनल ऐक्शन इन शुगर मिल मालिकों के खिलाफ लिए जिस से कि यह केन प्राइस अगले सीजन से पहले दी जा सके। क्या यह बात सही है और आप ने इस बात का असेसमेंट किया है कि किसी फैक्ट्री ने 35 परसेंट फी शुगर में से उस का कोई हिस्सा अपनी मिल के सुधार के लिए लगाया या खुद सरकार इन मिलों को फाइनेन्स देती रही है ? जैसे कि हमारे खुद के क्षेत्र में लगभग 20 लाख रुपया धुधली शुगर फैक्ट्री पर बकाया है और उत्तर प्रदेश सरकार 50 लाख रुपया उस को दे रही है और बैंक क्रेडिट गारन्टी देने की कोशिश कर रही है। इन बातों पर आप प्रकाश डालेंगे और बताएंगे कि किस तरह से केन ग्रोअर्स को सेटिसफाई करने जा रहे हैं ?

श्री शाहनवाज खां : यह सही है कि उत्तर प्रदेश में इस सीजन में कोई 8.81 करोड बकाया है लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि कुल खरीद एक सौ पचास करोड रुपये से ज्यादा है। इस तरह यह बकाया लगभग 3 परसेंट ही है।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : जो पैसा है उस का पेमेंट होना चाहिए, परसेंटेज का सवाल नहीं है।

श्री शाहनवाज खां : सही है। यू०पी० गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि जो मिल ओनर पेमेंट में दो हफ्ते से ज्यादा देर लगाते हैं उन्हें इसके ऊपर पीनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अभी वह 12 परसेन्ट है, आगे उस को 15 परसेंट करने की सोच रहे हैं। एकाध मिल मालिक को अरेस्ट भी किया गया है और जो ऐरियर्स थे वे "ऐज एरियर्स आफ़ लैंड रेवेन्यू रिकवर किए गए।" इसी तरह से सभी सरकारें मजबूत कदम उठा रही हैं।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : मैं ने जो सवाल किया उसका जवाब नहीं आया। मैं ने बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा था क्या सारे देश में केन ग्रोअर्स का मिलों पर लगभग 30 करोड रुपया बाकी है और उसमें 13 करोड उत्तर प्रदेश का है और वह बकाया केवल इसी सीजन का नहीं है बल्कि पिछले सीजन और उस से पहले सीजन का है तो इसके लिए इन मिल मालिकों के खिलाफ क्या पीनल ऐक्शन लिया गया ? क्या यह बात सही है कि आपने जो नीति निर्धारित की है फी शुगर के सम्बन्ध में उसके मुताबिक 50 परसेन्ट से तो केन ग्रोअर्स का बकाया पेमेन्ट किया जायेगा और बाकी 50 परसेन्ट से मिलों का सुधार किया जायेगा। अगर इस पचास परसेंट में केन ग्रोअर्स का पेमेंट नहीं किया तो आप ने क्या पीनल ऐक्शन लिया क्या यह बात भी सही है कि आप ने मेरे क्षेत्र के मिल मालिक को इसी सीजन में पचास लाख रुपया दिया ?

श्री शाहनवाज खां : इन के क्षेत्र के मिल मालिक को जो दिया गया है उस की जानकारी मुझे नहीं है। अगर माननीय सदस्य जानना चाहेंगे तो बाद में बता सकता हूं। जो रुपया सेस रिअलाइजेशन में से देना है वह मिनिमम स्टेच्यूटरी केन प्राइस के ऊपर देना होगा और चूंकि उत्तर प्रदेश में मिनिमम स्टेच्यूटरी प्राइस प्लस पचास परसेंट जो है उस से ज्यादा दिया जा चुका है तो उस में कोई ज्यादा बकाया नहीं है।

SHRI N K P SALVE Irrespective of the question of the percentage of recovery of sugar, sugar, for an average man like me, tastes sweeter if it can be available at a reasonable price, and that is how my supplementary comes What, according to the hon. Minister, is the reasonable price at which Government would intervene when the variation between the prices of levy sugar and the levy free sugar reaches a level which become sheer recketeering, profiteering and speculation?

Secondly is be sure that, purely by releasing sugar, the other economic forces would be taken care of, the

market forces would be taken care of so that the spiralling of prices in sugar will come down? The reasons have been mentioned by Shri Pandey: if the speculators and hoarders have sufficient capacity to keep in store large stocks, you may release any quantity, but that will have no effect

SHRI SHAHNAWAZ KHAN Firstly, there is a restriction on the quantity of sugar which may be retained by any one individual barring, of course, the mills where the total quantity is known to the Government—that is under the control of the Government The dealers are prohibited from keeping more than a certain quantity

When the price of levy free sugar starts going up then we release more levy free sugar in the market and the prices come down immediately We have for each of August and September released 30,000 tonnes more of levy free sugar

श्री सूरज पांडे : अध्यक्ष महोदय अभी तमाम देश में गन्ने के काश्तकारों में इस बात को लेकर काफी असंतोष है कि उन को गन्ने का उचित दाम नहीं मिलता क्यों कि इधर सरकार ने लगान भी बढ़ा दिया, खाद के दाम भी बढा दिए और मजदूरी के चार्जेज भी बढ गए लेकिन किसानों को जो गन्ने का दाम मिलता है वह बहुत कम है। पिछली दफा बजट अधिवेशन में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि गन्ने का दाम निर्धारित करने के लिए कोई खास पालिसी नहीं है बल्कि यह देखा जाता है कि उस एरिया में अगर किसान गन्ने के बजाय कोई दूसरा अनाज पैदा करता तो उस की क्या आमदनी होती और उसी के हिसाब से किसानों को दाम दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसा फारमूला बना रही है जिस से किसान को गन्ने का ठीक दाम मिल सके? इस समय किसान 20 रुपये पर क्विंटल का दाम चाहता है तो इस संबंध में सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री शाहनवाज खां : गवर्नमेंट ने इस मसले को हल करने के लिए कि गन्ने की और दूसरे अनाजों की कॉस्ट आफ प्रोडक्शन कितनी है एक कमेटी एपाइन्ट की है और ब्योरो आफ इंडस्ट्रियल कास्ट एण्ड प्राइसेज भी इस मामले को देख रहा है। उन्होंने एक सब-कमेटी एपाइन्ट की है जो सारे मसले को बडी गहराई के साथ देख रही है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले एक महीने या डेढ़ महीने में हमारे पास यह रिपोर्ट आ जाएगी।

MR SPEAKER Now the Question Hour is over

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Use of Imported Edible Oils in Manufacture of Vanaspati

*83 SHRI S R DAMANI Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state

(a) the reasons for recent issue of instructions for making larger use of imported edible oils in the manufacture of vanaspati,

(b) how is it going to affect production and cost of manufacture of vanaspati, and

(c) the action taken to ensure uninterrupted and timely supply of imported oils to the vanaspati manufacturing units?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SHAHNAWAZ KHAN) (a) To relieve the pressure on indigenous oils and to make available larger quantities of traditional indigenous oils for direct consumption, vanaspati manufacturers have been directed to use imported oils compulsorily to the extent of 50 per cent in the manufacture of vanaspati with effect from July 15, 1976